भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3071
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

भारत के सांख्यिकीय पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना

3071. श्री अरुप चक्रवर्तीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डेटा संग्रह तंत्र, सर्वेक्षण की गुणवत्ता, डेटा जारी करने में समयबद्धता और संस्थागत स्वायत्तता सहित भारत के सांख्यिकीय पारितंत्र की वर्तमान स्थिति और क्षमता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जनशक्ति, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और केंद्रीय तथा राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों के बीच समन्वय से संबंधित उन कमियों की पहचान की है जो आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को प्रभावित करती हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का उन्नत डेटा प्रौद्योगिकियों को अपनाने, सांख्यिकीय कर्मियों के क्षमता निर्माण, बेहतर पारदर्शिता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन जैसे सुधारों के माध्यम से भारत के सांख्यिकीय पारितंत्र को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): विकसित हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र में, सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता का आकलन और संस्थागत सुधार इसे अद्यतन रखने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने आधिकारिक आंकड़ों की गुणवत्ता, आवृत्ति, समयबद्धता, बारीकी, सामंजस्य और सुलभता को बढ़ाकर भारत के सांख्यिकीय तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया गया है, जो ई-सिग्मा प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है और इसमें अंतर्निहित सत्यापन जांच, एआई-सक्षम चैटबॉट और बहुभाषी इंटरफेस आदि शामिल हैं। एमओएसपीआई ने उच्च आवृत्ति वाले सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम अवधि के सर्वेक्षण शुरू किए हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार संशोधन सहित व्यापक आर्थिक सांख्यिकी में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। एमओएसपीआई ने व्यापक डेटा सामंजस्य/मानकीकरण पहल की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (एनएमडीएस 2.0)को अपनाना, सांख्यिकीय गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएएफ) शुरू करना और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण मानकों के साथ संरेखण शामिल है। एमओएसपीआई की नई वेबसाइट, जीओआई स्टैट्स के मोबाइल एप्लिकेशन, ई-सांख्यिकी पोर्टल, माइक्रोडाटा पोर्टल और डेटा आदान-प्रदान के लिए एपीआई के उपयोग से डेटा का प्रसार और सुलभता काफी हद तक बढ़ाई गई है। एमओएसपीआई ने 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए पैमाना (राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना पर्यवेक्षण और विश्लेषण) नामक एक नई वेब-आधारित निगरानी प्रणाली भी शुरू की है।

एमओएसपीआई अपनी सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य उप-राज्य स्तर पर विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए राज्य सांख्यिकी प्रणाली की सांख्यिकी क्षमता और संचालन में सुधार/ सुदृढ़ीकरण करना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), जो एमओएसपीआई के अंतर्गत एक प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, केंद्रीय और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सांख्यिकी कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल उपकरणों, डेटा विश्लेषण और डेटा प्रबंधन सहित "आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित क्षेत्रों" पर नियमित आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि संबंधित क्षेत्र से बेहतर डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एमओएसपीआई ने सम्मेलनों, परामर्शों, कार्यशालाओं और प्रतिक्रिया तंत्रों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी एजेंसियों के बीच समन्वय को भी सुदृढ़ किया है।

*****